एम० ई० एस० प्राधिकारियों द्वारा तकनीकी रूप से मंजूर इस परियोजना पर लागत 17,08,978 रुपये की आयेगी। यह धनराशि सरकार द्वारा फरवरी 1984 में पहले ही मंजूर कर दी गई है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में हिन्दी का प्रचार

206. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों के न तो अध्यक्ष हो और न प्रबन्ध निदेशक ही हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकों में भाग लेते हैं जिससे इन बैंकों में हिन्दी के विकास, प्रचार और प्रसार में बाधा पड़ रही है;

(ख) क्या यह सच है कि भाग 'क' क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में तथा अधिसूचित कार्यालयों में जहां मूल काम मात्र हिन्दी में ही किया जाना चाहिये, हिन्दी में यह काम अभी प्रारम्भ नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार रखती है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) चूंकि 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्ष एवं पदेन निदेशक वित्त मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्य नहीं हैं इसलिए वे समिति की बैठकों में भाग नहीं लेते। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर इस समिति के सदस्य हैं और उनकी अनुपस्थिति में बैंक के उप गवर्नर/कार्यपालक निदेशक बैठक में भाग लेते हैं। गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार इस समिति की सदस्य संख्या 30 तक ही सीमित है। बैंकों के अध्यक्षों को इस समिति का सदस्य बना दिए जाने से समिति का संचालन करना सहज नहीं रहेगा।

प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक की क्षेत्र/मंडल/अंचल और प्रधान कार्यालय स्तरों पर अपनी-अपनी राजभाषा कार्यान्वयन समितियां होती हैं जिनकी अध्यक्षता सम्बद्ध कार्यालयों के प्रमुख करते हैं। इन समितियों की बैठकें नियमित रूप से होती हैं जिनमें राजभाषा के प्रयोग के संबंध में समीक्षा की जाती है और काम में सुधार करने के लिए सुझाव दिए जाते हैं।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों और 1983-85 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार बैंकों से "क" क्षेत्र में 66.7 प्रतिशत तक मूल पत्राचार हिन्दी में करने के लिए कहा गया है। राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अधीन शाखाएं अधिसूचित करने के अलावा कुछ बैंकों ने अपनी कुछ ऐसी ग्रामीण शाखाओं का भी चयन किया है जहां सारा काम हिन्दी में ही किया जाना है।

इस संबंध में बैंकों के काम पर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तिमाही रिपोर्टों के जरिए बराबर नजर रखी जाती है और जब कभी कोई त्रुटि दिखाई देती है तब संबंधित बैंक के अध्यक्ष को उपचारात्मक उपाय करने के लिए कहा जाता है।

Vayudoot service in different places of Maharashtra

207! SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state*.

(a) what is the progress so far made in starting the Vayudoot set-